सरोकारों से साक्षात्कार

रीजनल रिपोर्टर

पृष्ठ : 04
स्थापित : 2008
संस्थापक: स्व. बी. शंकर
04 जुलाई 2025, शुक्रवार
संपादक: गंगा असनोड़ा: 9412079290

श्रीनगर (गढ़वाल), उत्तराखण्ड से प्रकाशित, साप्ताहिक आर.एन.आई.नं: UTTHIN/2008/24749, वर्ष: 16, अंक: 51, मूल्य: 10

डांग में हाट बाजार के विरोध में उतरी व्यापार सभा

गंगा असनोड़ा

श्रीनगर से सटा डांग क्षेत्र 2019 के नागर निकाय चुनावों से पूर्व नगरपालिका में शामिल कर लिया गया। वर्तमान में यह क्षेत्र श्रीनगर नगर निगम का हिस्सा है। इस क्षेत्र से फरवरी 2025 में चयनित हुए नगर निगम बोर्ड में पांच वार्डो के पार्षद चुने गए हैं। डांग ऐठाणा के इन पांच पार्षदों को तय करना है कि उनके क्षेत्र में किस तरह के विकास कार्य होने चाहिए। श्रीनगर के विभिन्न वार्डो में हाट बाजार लगाने का प्रस्ताव नगर निगम बोर्ड द्वारा पूर्व में ही पारित हो चुका है। इस संदर्भ में नगर निगम की ओर से सबसे पहले डांग क्षेत्र में हाट बाजार लगाने का प्रयास हो रहा है, लेकिन स्थानीय व्यापारी इस निर्णय के विरोध में उतर आए हैं। व्यापार संघ अध्यक्ष सौरभ पांडे ने कहा कि यह वर्षो से डांग क्षेत्र में रह रहे व्यापारियों के साथ धोखा है।

श्रीनगर व्यापार संघ ने भी डांग व्यापार सभा के विरोध को अपना समर्थन दिया है। हालांकि हाल ही में नगर निगम बोर्ड से निर्वाचित पार्षदों ने एक स्वर में हाट बाजार लगाए जाने का समर्थन जताया है।

वृहस्पतिवार को इस संदर्भ में मेयर आरती भंडारी को स्थानीय लोगों तथा पार्षदों ने ज्ञापन भी सौंपा। वार्ड संख्या 32 के पार्षद पंकज सती इसका पुरजोर समर्थन कर रहे हैं।

मेयर आरती भंडारी का कहना है कि उन्हें स्थानीय बेराजगारों, स्थानीय व्यापारियों तथा जनहित में कार्य करना है। इसी आधार पर नगर निगम बोर्ड में प्रस्ताव पारित किए गए हैं।

भले ही नगर निगम बोर्ड की ओर से हाट बाजार लगाए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ हो, लेकिन वर्तमान में व्यापार सभा के विरोध को देखते हुए, नगर निगम, डांग में हाट बाजार नहीं, बल्कि सिर्फ सब्जी और फलों की ठेलियां लगाने की मुहिम चलाता नजर आ रहा है। अब देखना यह होगा कि अलग-अलग क्षेत्रों में फल-सब्जियों के लिए थोक बाजार लगाने से स्थानीय फल एवं सब्जी व्यापारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या इनके नुकसान के लिए भी कोई आवाज उठाएगा?

विरोध भी और समर्थन भी

नगर निगम में शामिल हुए डांग क्षेत्र के लोगों ने नगर निगम कार्यालय में पहुंच कर मेयर आरती भण्डारी से डांग में हाट बाजार लगाए जाने की मांग की। क्षेत्रवासियों की इस मांग पर पार्षदों ने भी अपना समर्थन व्यक्त किया है। ■■■

केन्द्र सरकार ने किया 3.5 करोड़ लोगों को नौकरी का वायदा

अमीषा गोस्वामी

केंद्र सरकार ने 1.07 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (ईएलआई) को मंगलवार को मंजूरी दे दी। इसका उदेश्य सेवानिवृत्ति निधि निकाय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से अगले दो वर्ष में 3.5 करोड़ नौकरियों का सृजन करना है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसका उद्देश्य सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता में वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना है।

इस योजना का उद्देश्य दो साल में देश में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहन देना है। इसके अलावा, यह योजना पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन देगी। इस योजना के तहत पहली बार नौकरी पर रखे गए कर्मियो को एक महीने का वेतन (15,000 रुपये तक) मिलेगा। वहीं नियोक्ताओं को अतिरिक्त रोजगार सृजन के लिए दो साल की अवधि के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा।

पहली नौकरी में ऐसे लोग आते हैं, जसने अभी तक कभी भी ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है,। जिसने अब तक किसी भी सरकारी या प्राइवेट कंपनी में औपचारिक तरीके से काम नहीं किया है, जहाँ ईपीएफ कटता हो।

यानी उसकी कोई ईपीएफ एंट्री अभी तक नहीं हुई है।

कौन हैं ऐसे व्यक्ति

- कॉलेज से नये ग्रेजुएट छात्र।
- गृहणी या बेरोजगार, जो पहली बार नौकरी में आ रहे हों।
- ऐसे लोग जो पहले अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते थे और अब औपचारिक क्षेत्र में आ रहे हैं। ■■■

त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए अधिसूचना जारी

स्टेट ब्यूरो

उत्तराखंड सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। हरिद्वार को छोड़कर प्रदेश के 12 जिलों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद रुके चुनाव अब नए कार्यक्रम के अनुसार दो चरणों में होंगे।

इस बार पूरे प्रदेश में 66,418 पदों पर चुनाव होंगे। इनमें ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य शामिल हैं।

राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया को दो चरणों में विभाजित किया है, लेकिन दोनों चरणों की मतगणना एक ही दिन 31 जुलाई 2025 को की जाएगी। चुनाव का यह शेड्यूल न केवल सुव्यवस्थित है, बल्कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से व्यावहारिक भी है।

चुनाव कर्मचारियों की तैनाती सॉफ्टवेयर से रेंडम आधार पर की जाएगी। अवैध शराब, नकदी या अन्य सामान की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन, पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीमें तैनात होंगी। खर्चो की निगरानी के लिए हर जिले में एक व्यय अधिकारी भी नियुक्त होगा।

इस बार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कुल 47,77,072 मतदाता वोट डालेंगे। इनमें पुरुष, महिला और तीसरे लिंग के मतदाता शामिल हैं। साल 2019 के मुकाबले 10.57 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। करीब 4.5 लाख नए मतदाता जुड़े हैं। पूरे चुनावी कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए 95,909 अधिकारी-कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के लिए 35,700 जवान लगाए जाएंगे। इसके अलावा 67 चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे।

66418 पदों पर होंगे चुनाव

- जिला पंचायत सदस्य-358
- क्षेत्र पंचायत सदस्य- 2,974
- ग्राम पंचायत सदस्य- 55,587
- ग्राम प्रधान- 7,499

चुनावी शेड्यूल

- 2 से 5 जुलाई तक पहले चरण के लिए नामांकन।
- 7 से 9 जुलाई तक नामांकन पत्रों की जांच।
- 10-11 जुलाई तक नाम वापसी की अंतिम तिथि।
- 14 जुलाई को प्रथम चरण के लिए चुनाव चिन्ह आवंटन।
- 18 जुलाई को द्वितीय चरण के चुनाव चिन्ह आवंटन।
- 24 जुलाई को पहले चरण का मतदान।
- 28 जुलाई को दूसरे चरण का मतदान।
- 31 जुलाई को प्रथम और द्वितीय चरण की मतगणना का परिणाम घोषित।

मत्रपत्र रंग

- मतपत्रों का रंग आवंटित
- जिला पंचायत सदस्य -गुलाबी
- क्षेत्र पंचायत सदस्य - नीला
- ग्राम पंचायत सदस्य- सफेद
- ग्राम प्रधान- हरा ■■■

24 को पहले 28 जुलाई को दूसरे चरण में होगा मतदान

24 जुलाई को पहले चरण में कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, उधमसिंह नगर के 23 ब्लॉकों के लिए , जबकि गढ़वाल मंडल में चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, देहरादून, रुद्रप्रयाग के 26 ब्लॉकों के चुनाव संपन्न होंगे।

28 जुलाई को दूसरे चरण में कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल, उधमसिंह नगर के 18 ब्लॉकों तथा गढ़वाल मंडल के उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग के 22 ब्लॉकों में मतदान होगा।

नैनी झील में फिर दिखी प्रतिबंधित मांगुर मछली

स्टेट ब्यूरो

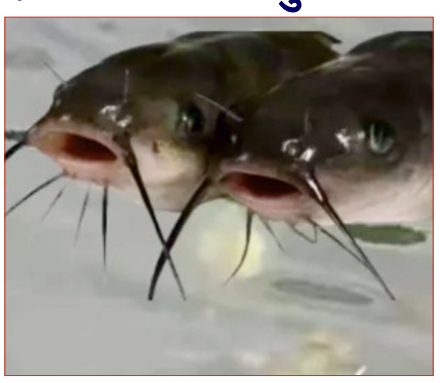

उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित नैनी झील में एक बार फिर प्रतिबंधित और खतरनाक मांगुर मछली देखे जाने की सूचना ने हड़कंप मचा दिया है। यह वही मछली है जिसकी खेती को भारत सरकार ने वर्ष 2000 में पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया था।

नैनी झील के एरिएशन केंद्र के प्रोजेक्ट मैनेजर आनंद सिंह कोरंगा ने झील में मांगुर मछली देखे जाने की पुष्टि की है। इस जानकारी को उन्होंने जिला विकास प्राधिकरण के सचिव विजयनाथ शुक्ल और पंतनगर विश्वविद्यालय के मत्स्य विभाग के अधिकारियों को भी दी है। इससे झील की सुरक्षा और जैव विविधता को लेकर चिंता और सतर्कता बढ़ गई है।

मांगूर मूलत: थाईलैंड की प्रजाति है। यह कैटफिश वर्ग की मछली है जो हवा में सांस ले सकती है, सूखी जमीन पर चल सकती है और कीचड़ में भी जिंदा रह सकती है। इसकी लंबाई 3 से 5 फीट तक हो सकती है और यह तेजी से प्रजनन करके अपनी संख्या बढ़ा लेती है। यह आमतौर पर मांसाहारी होती है और जलाशयों में पाई जाने वाली देशी प्रजातियों की मछलियों को खा जाती है। माना जाता है कि यह देशी मछली प्रजातियों की 70 प्रतिशत तक की गिरावट के लिए जिम्मेदार है। इसकी खेती में सड़े-गले मांस का उपयोग होता है, जिससे जल प्रदूषण और झीलों के जैविक संतुलन को गंभीर खतरा होता है। इसलिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इसे पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए घातक मानते हुए इसकी खेती पर रोक लगा दी थी।

2008-09 में भी एक मामला सामने आया था, जिसमें एक व्यक्ति ने धार्मिक मान्यता के चलते अपनी बीमार माँ की सलामती की कामना में नैनी झील में मांगुर मछलियाँ छोड़ी थीं। उस समय ज्यादातर मछलियाँ निकाल दी थीं, लेकिन चर्चा थी कि कुछ झील में बच गई थीं। अब एक बार फिर लगभग 15 साल बाद, इन मछलियों के देखे जाने की रिपोर्ट सामने आई है। ■■■

SUBSCRIBE

संपादकीय

योग के लिए जरूरी है पृथ्वी का वजूद

त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए उच्च न्यायालय की हरी झंडी मिलने के बाद जारी अधिसूचना में उत्तराखंड के पंचायती चुनाव दो चरणों में होने की अधिसूचना जारी हुई है। जिस तरह छह माह देर से पंचायत चुनाव कराने के लिए सरकार ने कमर बरसात के मौसम में कसी है, वह आने मतदाताओं तथा मतदान ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को नाकों चने चबाने वाला निर्णय साबित हो सकता है।

जून माह में अब तक हुई बारिश ने राज्य की जो तस्वीर सबके सम्मुख रखी है, वह हालात बेहद गंभीर प्रदर्शित करता है। सोशल मीडिया के इस दौर में कंधे पर राशन लादे उफनती नदियों को पार करते ग्रामीण हों या पीसीएस की परीक्षा देने के लिए जान जोखिम में डालकर नदी पार करते युवा बेरोजगार। जगह-जगह बारिश के कारण हुए भूस्खलन से जाम हुई सड़कें हों या अतिवृष्टि से पुलों और सड़कों के बह जाने की घटनाएं, सब आने वाली बरसात में पंचायत चुनाव कराने के निर्णय को एक दूरदर्शी निर्णय तो कतई नहीं साबित कर सकता।

बहरहाल! जो भी हो, आपदाओं का उत्तराखंड से चोली-दामन का सा साथ रहा है। उत्तराखंड में बीते दो दशकों में निर्मित या निर्माणाधीन परियोजनाओं ने उत्तराखंड के नीति-नियंताओं तथा नियोजनकर्ताओं की क्षमताओं तथा काबिलियत को जगजाहिर किया है। बनते हुए पुलों का टूट जाना हो या निर्माण के दा-चार साल के भीतर टूटना, किसी अधिशासी अभियंता का सर्विस बुक खो जाने पर दो मुट्ठी चावल की मांग करने से लेकर सिरोबगड़ जैसी दुधारू योजनाओं का हरा हो जाना इस हकीकत को बयां करता है।

दो दशक पहले के उत्तराखंड को याद किया जाए, तो अकेले ऋषिकेश-बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब 10 स्थानों पर सेंसिटिव जोन चिन्हित किए गए थे, लेकिन आज इसी राजमार्ग पर कभी चार धाम परियोजना, तो कभी ऑल वेदर रोड के नाम पर सड़क चौड़ीकरण के लिए किए गए अंधाधुध डायनामाइटों के इस्तेमाल तथा अन्य विध्वंसक उपकरणों के प्रयोग से अनगिनत संवेदनशील क्षेत्र चिन्हित कर लिए गए हैं।

यह सब अदूरदर्शी नीतियों का परिणाम ही तो है। सुखद यह है कि उत्तराखंड में छह माह से सूनी पड़ी पंचायतें गुलजार होने जा रही हैं। रोस्टर प्रक्रिया में निसंदेह राज्य सरकार ने असंवैधानिक प्रक्रिया अपनाई है, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती भी मिली। हाईकोर्ट ने चुनावों पर तीन दिन स्टे लगाने के बाद उसे खोल दिया। संभवतः कोर्ट पंचायतों के गठन में बाधक नहीं बनना चाहता था। ■■■

याचिकाओं पर चुनाव के बाद सुनवाई असमंजस भरा निर्णय

इंद्रेश मैखुरी

नैनीताल उच्च न्यायालय द्वारा बीती 23 जून को लगाई गयी रोक को 27 जून को हटाए जाने के बाद उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का संशोधित कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 12 जिलों में दो चरणों में 24 जुलाई और 28 जुलाई को मतदान होना है तथा 31 जुलाई को मतगणना होगी।

इस संशोधित कार्यक्रम की रोचक बात यह है कि इसमें दोनों चरणों की सिर्फ मतगणना की तारीख ही समान नहीं है बल्कि नामांकन, नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की तारीखें भी दोनों चरणों के लिए समान ही हैं। केवल चुनाव चिन्ह आवंटन और मतदान की तिथि ही अलग हैं दोनों चरणों में क्यों? पता नहीं !

घोषित कार्यक्रम के अनुसार पंचायत चुनावों के नामांकन की प्रक्रिया 2 जुलाई से शुरू होगी। यह मॉनसून सीजन है। चारों तरफ भूस्खलन, सड़कों के बंद होने आदि की खबरें हैं। ये चुनाव सात महीने विलंब से हो रहे हैं। मुमकिन था कि वे सूखे- निरापद मौसम में कराए जाते, लेकिन वे भारी बारिश के बीच कराए जा रहे हैं, जो चुनाव लड़ने वालें चुनाव ड्यूटी करने वालों और मतदाताओं के लिए जोखिम का सबब बनेंगे। इसका कोई जवाब नहीं कि चुनाव कराने के लिए मॉनसून सीजन ही क्यों चुना गया।

लोग कह रहे हैं पंचायत चुनाव दो चरणों में कराना, एक देश- एक चुनाव वाले नारे का मखौल है! यह मखौल हो न हो पर एक राज्य के 12 जिलों के लिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अलग और एक जिले के लिए अलग, यह तो मजाक है ही! गौरतलब है कि उत्तराखंड में हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और शेष 12 जिलों में पंचायत चुनाव अलग अलग होते हैं।

इन पंचायत चुनावों की प्रक्रिया शुरू होते ही लोग आरक्षण के रोस्टर आदि की विसंगतियों और उसमें सरकार की मनमानी से त्रस्त हो कर उच्च न्यायालय गए। शुरुआती तौर पर न्यायालय ने विसंगतियों को देखते हुए इन चुनावों पर स्टे भी लगा दिया, लेकिन अब यह स्टे हटा लिया गया है।

उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत जिला पंचायत की सीटों के चार्ट को देख कर यह मान लिया कि आरक्षण के प्रावधानों का ठीक से पालन हुआ है और चुनाव कराने की अनुमति दे दी। आम तौर पर देखें तो आरक्षण नियमों से ज्यादा सत्ता पक्ष की सहूलियत से निर्धारित होता है। इसलिए ऐसी सीटें त्रिस्तरीय पंचायतों और नगर निकायों में भी मिल जायेंगी, जो कभी आरक्षित नहीं हुई यानि अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला आदि को कभी इन सीटों पर प्रतिनिधित्व का अवसर ही नहीं मिला।

अदालत के सामने प्रस्तुत विभिन्न याचिकाओं में इस पूरी प्रक्रिया में सरकार द्वारा बरती गयी मनमानी और वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के मामले प्रस्तुत किये गए थे। इसमें सबसे प्रमुख मामला तो पुराने रोस्टर को खत्म करके बनाई गयी नई नियमावली का है। उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम की धारा 126(3) में स्पष्ट प्रावधान हैं कि राज्य सरकार पंचायतों के संबंध में कोई भी नियम राज्य की विधानसभा के अनुमोदन के बाद गजट में प्रकाशित करके लागू कर सकती है, लेकिन नई आरक्षण नियमावली के मामले में तो ऐसा हुआ नहीं।

गजट नोटिफिकेशन भी पहले दिन उत्तराखंड सरकार कोर्ट में पेश नहीं कर सकी। बहाना किया गया कि कम्युनिकेशन गैप हो गया। जबकि 23 जून को कोर्ट के स्टे के बाद पंचायत राज सचिव का बयान था कि सरकारी प्रेस से एक प्रति छाप कर देने को कहा गया है।

उच्च न्यायालय में लगभग 53 याचिकाएं पंचायत चुनाव को लेकर दाखिल की गई थी। 27 जून के अदालत के 9 पन्नों के फैसले में डेढ़ पन्ना तो इन याचिकाओं के उल्लेख पर ही लगा था।

ये सारे प्रश्न तो अभी खड़े ही हैं, इन पर सुनवाई भी चलेगी पर पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद इन पर सुनवाई या फैसले का क्या औचित्य रह जाएगा ? क्या वह न्याय होना माना जाएगा या क्या उससे न्याय होता दिखाई भी देगा ? ■■■

सकारात्मक परिवर्तन का दौर

नीमा पाठक

एक बार स्वामी रामतीर्थ जापान गए। उन दिनों वे भोजन में फल ही खा रहे थे, लेकिन उन्हें वहां फल उपलब्ध नहीं हुए। उन्होंने किसी को कहा, "शायद जापान में फल नहीं मिलते" उनकी बात वहां खड़े जापानी ने सुन ली। उसने उनके होटल का पता पूछा और काफी मात्रा में फल लेकर वहां पहुंच गया। स्वामी जी ने फलों की कीमत पूछी, तो उसने कहा, "बस आप भारत जा कर ये मत कहिए कि जापान में फल नहीं मिलते हैं।" यह कहानी पहले देश प्रेम की मिसाल के तौर पर विद्यालयों में पढ़ाई जाती थी। एक समय ऐसा था जब हमारे देश के लोगों को विदेश की चीजें बहुत आकर्षित करती थीं। वहां की कहानियां, वहां के कपड़े, सामान, भाषा सब कुछ अपने से बेहतर लगता था।

बाहर से आया व्यक्ति वहां का गुणगान करते नहीं थकता। कुल मिलाकर विदेशी श्रेष्ठ और हम निकृष्ट। ऐसे दौर में इस तरह की कहानियां सुन कर उनकी श्रेष्ठता का भान होता था। अब समय ने करवट ली है हम भारतीय इस तरह की हीन भावना से उबर कर इतने सक्षम हो गए हैं कि अपनी हानि-लाभ को परे रख अपने देश के हित में देश के स्वाभिमान के लिए मजबूत कदम उठाने लगे हैं।

तुर्की की पाकिस्तानपरस्ती देखकर जिस तरह से व्यापारियों ने वहां के फलों और संगमरमर का व्यापार बंद करने का निर्णय लिया और 'मेक माई ट्रिप' ने सारे टिकिट कैंसिल किए, एक स्वागत योग्य व गौरवान्वित करने वाला निर्णय है, जो देश हमारे दुश्मन से हाथ मिलाएं। हम उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करें। ये तो देशद्रोह जैसा है। ऐसा एक सैलानी का कहना था, जिसने अपनी तुर्की की बुकिंग कैंसिल की थी।

सरकारी फैसले का इंतजार किए बगैर देशहित में स्वयं निर्णय लेना जनता की जागरूकता का प्रमाण है। सरकारी फैसले भी फाइलों में बंद रह जाते हैं, जब तक जनता साथ नहीं देती है। सकारात्मक परिवर्तन का दौर है।, एक दुर्घटना या वारदात बहुत बड़ी एकता का संदेश भी साथ में लाती है, जिसका उदाहरण पहलगाम का आतंकी हमला है, जिसका देश ने पूरी एकजुटता के साथ सामना किया ■■■

एसके बिजल्वान बने रोटरी क्लब के अध्यक्ष

रीजनल रिपोर्टर ब्यूरो

रोटरी क्लब अलकनंदा वैली की नए सत्र की बैठक में रोटेरियन एसके बिजल्वान अध्यक्ष, नवल किशोर जोशी व सुनील बागड़ी को कोषाध्यक्ष चुना गया।

इस अवसर पर निवर्तमान अध्यक्ष अर्जुन सिंह गुसांई ने नवनियुक्त अध्यक्ष व सचिव को बधाई देते हुए विगत रोटरीसत्र में हुए कार्यों एवं सहयोग के लिए सभी सदस्यों का धन्यवाद दिया, जबकि नव नियुक्त अध्यक्ष रो.बिजल्वाण ने आगामी वर्ष के लिए योजना का प्रारूप रखा।

कार्यक्रम को डा.एसडी जोशी, प्रो.एसपी काला, वेदव्रर्त शर्मा आदि ने भी सम्बोधित किया।

कलब में प्रो.वाईपी रेवानी,, धनेश उनियाल, मेहरबान सिंह रावत, चंद्रभानु तिवारी, डॉ.वरुण को भी क्लब पदाधिकारी की जिम्मेदारी दी गई।

इस मौके पर पीबी नैथानी, डॉ बीपी चौधरी, पूनम जोशी, ओमप्रकाश बधानी, अजय प्रकाश जोशी, डा प्रशांत पंवार, कृपाल सिंह पटवाल, धन राज बुटोला, डॉ. राहुल बहुगुणा आदि मौजूद थे। ■■

पंचायतों चुनाव ऐगी

पंचायतों चुनाव ऐगौ,
सुकिल टोपि का मुनाव ऐगीं।
मैं कैं जिताओ, मैं कैं जिताओ हैरे,
अजकाल हमर गौंनूपन बहार ऐरै।
गौंनूपन क्वे पांणि ल्याऔ नि ल्याऔ
सभापति मुखम पांणी ऐगौ।
पंचायतों चुनाव ऐगौ।
एक जै प्रधान, पंद्र जै उम्मीदवार है गई
यौस लागण जस यांका नेता लै
बेरोजगार है गई। ■■■

आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार है।
अपनी प्रतिक्रिया इस पते पर भेजें।
9412079290, 7037548484
regionalreporter81@gmail.com

श्री कम्यूनिकेशन के लिए गंगा असनोड़ा थपलियाल द्वारा 15 फालतू लाईन, समय साक्ष्य देहरादून से मुद्रित एवं 76, अपर बाजार श्रीनगर से प्रकाशित।
न्यायिक क्षेत्र : श्रीनगर गढ़वाल
संस्थापक संपादक : स्व. बी. शंकर
सलाहकार: वीरेन्द्र कुमार पैन्यूली
संपादक : गंगा असनोड़ा थपलियाल
विशेष प्रतिनिधि : उमा घिल्डियाल
स्टेट ब्यूरो : भारती जोशी
विशेष प्रतिनिधि (गैरसैण) : भैरव दत्त असनोड़ा

कार्यालय : श्री कम्यूनिकोशन 76, अपर बाजार, श्रीनगर गढ़वाल-246174
आर.एन.आई.न.-
UPHIN/1999/863

चौंक गई जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया

रीजनल रिपोर्टर ब्यूरो

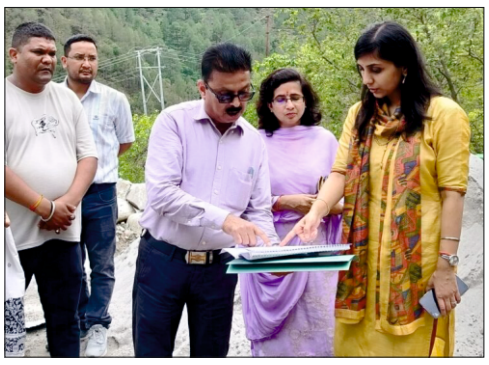

पौड़ी की नवनियुक्त जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने श्रीनगर नगर क्षेत्र के विभिन्न स्थलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने गंगा दर्शन बैंड स्थित गौशाला, निर्माणाधीन एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) सेंटर, गंगा संस्कृति केंद्र, अलकेश्वर घाट, श्रीनगर तहसील व चारधाम यात्रा कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया।

गौशाला निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्माणाधीन एबीसी सेंटर को विस्तारित करने और पशु रख-रखाव के लिए गाइडलाइन अनुसार समिति गठन के निर्देश दिये। साथ ही नगर निगम को निर्देश दिये कि भवन तैयार होने तक मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी के समन्वय से आवश्यक उपकरणों को खरीदे जाने की प्रक्रिया पूर्ण करें। साथ ही उन्होंने कहा कि सेंटर के संचालन हेतु तात्कालिक व्यवस्था के रूप में पशुपालन विभाग द्वारा पशु चिकित्सक उपलब्ध करा दिया जायेगा। गौशाला का भी निरीक्षण कर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देश दिये कि टैग लगे हुए आवारा पशुओं के स्वामियों की पहचान करते हुए उन पर चालानी कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। ग्राम स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी गायें खुली सड़कों पर न छोड़ी जाएं।

तहसील निरीक्षण में डीएम ने साफ-सफाई बनाये रखने और अवसंरचना विकास हेतु कार्ययोजना तैयार कर जिला कार्यालय में प्रस्तुत करने को कहा। संग्रह अनुभाग में बड़े बकायेदारों से वसूली प्रक्रिया तेज करने के निर्देश अमीन को दिये।

अलकेश्वर घाट पर निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त को स्वच्छता व्यवस्था सुदृढ़ करने, चेंजिंग रूम की मरम्मत, पेयजल सुविधा मजबूत करने और सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिये। उन्होंने सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तावित बाढ़ सुरक्षा दीवार की डीपीआर की जानकारी ली और कहा कि दीवार को तेज बहाव से सुरक्षित रखने के लिये इसे और मजबूत किया जाय। साथ ही नदियों के कटाव को रोकने के लिए तकनीकी सुझावों के आधार पर स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। ■■■

पीड़ी के जंगल में दिखा रेड डाटा सूची का पॉम सीवेट

महीपाल नेगी

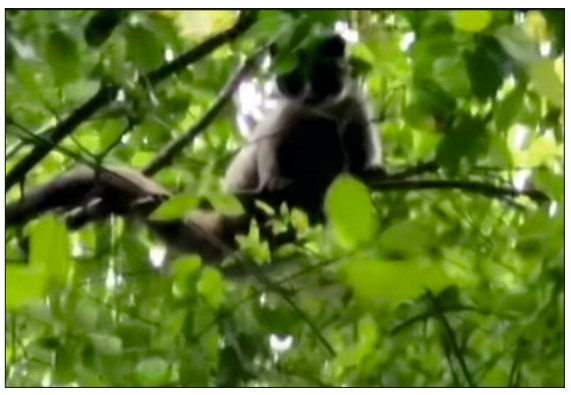

यह एक दुर्लभ माने जाने वाला जीव 'हिमालयन पॉम सिवेट' है, जिसे हम भारतीय लोग कस्तूरी बिडाल नाम से भी जानते हैं। वर्ष 2008 में इसे खतरे में आ रहे दुर्लभ जीव-जंतुओं की रेड सूची में शामिल किया गया था।

टिहरी जिले के प्रतापनगर व जाखणीधार विकास खण्ड में फैले पीड़ी पर्वत, जिसे कई बार स्थानीय लोग खैट पर्वत या खैट पीड़ी के संयुक्त नाम से पुकारते हैं, के जंगल में इस जीव को हमारे साथी धारकोट गांव के पूर्व प्रधान योगेंद्र नेगी, गुड्डू भाई ने कैमरे में कैद किया।

गुड्डू भाई पहले भी इस जंगल में कैट लेपर्ड व सरौं आदि दुर्लभ जंतुओं को देख व कैमरे में भी ले चुके हैं। धारकोट, पटुडी व कफलोग आदि गांवों से लेकर प्रतापनगर व दूसरी ओर ढुंग मंदार तक फैले खैट पीड़ी के दुर्गम जंगल में दुर्लभ जंतुओं का दिखना अच्छी बात है।

पीड़ी पर्वत व भराड़ी मंदिर तक लोग जंगल के रास्तों से जाते हैं। इस तरफ भी जंगल में आग लगती रही है, हालांकि इस वर्ष ज्यादा आग नहीं लगी। हो सकता है, इस कारण दुर्लभ जीव जंतु कुछ सहज महसूस कर रहे हों। वैसे तो यह जीव मांसाहारी है, जो पक्षी, चूहे, सांप आदि खाता है लेकिन जंगली फल और कुछ पत्तियों को भी भोजन बनाता है।

अब तक रेड सूची के तीन जीव जंतु -कैट लेपर्ड, सरौं और अब यह हिमालय पॉम सीवेट। एक ही जंगल में और वह भी टिहरी के काफी निकट। गुड्डू भाई जंगल और दुर्लभ जीव - जंतुओं पर अध्ययन करते रहते हैं। कभी खैट पीड़ी की ट्रैकिंग करनी हो तो इन्हें गाइड बनाया जा सकता है।

बता दें कि पीड़ी पर्वत के एक छोर की ओर ही खैट शिखर है, जहां आछरियों (वन देवियों) का निवास माना जाता है। ■■■

रोटरी क्लब श्रीनगर ने चिकित्सकों को किया सम्मानित

सीताराम बहुगुणा

रोटरी क्लब श्रीनगर गढ़वाल द्वारा आयोजित भव्य समारोह में डॉक्टर्स डे के अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सकों को सम्मानित किया गया। संयुक्त अस्पताल में सीनियर फिजिशियन डॉ.सुरेश कोठियाल एवं वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉ.गोविंद पुजारी को वोकेशनल अवॉर्ड से नवाजा गया।

कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। संयोजक रो डॉ.केके गुप्ता ने डॉक्टर्स डे के महत्व पर प्रकाश डाला। अपने संबोधन में डॉ.सुरेश कोठियाल ने कहा कि,, 'डॉक्टर्स डे महज एक तारीख नहीं,, बल्कि वह दिन है, जो सेवा, समर्पण और संघर्ष को सलाम करता है, जिसे हर डॉक्टर प्रतिदिन निभाता है।'

इस अवसर पर डॉ.दयाकृष्ण टम्टा, डॉ.सुशांत मिश्रा, डॉ.रचित गर्ग, डॉ.दिग्पाल दत्त, डॉ.अंकिता पैन्यूली, डॉ. मोहित सैनी, डॉ. गरिमा नैथानी, डॉ.निधि बहुगुणा, डॉ.मोहित कुमार, डॉ.प्रशांत मैठाणी, डॉ.शुभम बंगवाल, डॉ.शशांक ममगांई, डॉ. अर्पित बहुगुणा तथा डॉ.दिव्यांशु थपलियाल को भी सम्मानित किया गया।

असिस्टेंट गवर्नर रो.बृजेश भट्ट ने रोटरी के उद्देश्यों और समाज में उसकी भूमिका की जानकारी दी। क्लब अध्यक्ष रो.हिमांशु अग्रवाल ने सभी सम्मानित चिकित्सकों एवं अतिथियों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम का संचालन रो.खिलेंद्र चौधरी ने किया।

इस अवसर पर सचिव रो. संजय रावत, कोषाध्यक्ष रो.मनीष कोठियाल, रो.नरेश नौटियाल, रो. अनूप घिल्डियाल, रो.एस.पी. घिल्डियाल, रो.दिनेश जोशी, रो. राहुल कपूर सहित बड़ी संख्या में रोटेरियन उपस्थित रहे। ■■■

पंचायत चुनावों के लिए बिछने लगी बिसात

लक्ष्मण सिंह नेगी

ऊखीमठ विकासखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की नामांकन प्रक्रिया विधिवत शुरू हो गयी है। नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन नामांकन करने वालों तथा नामांकन प्रपत्र खरीदने वालों का तांता लगा रहा तथा ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिला। पूरे विकासखंड में 846 वार्ड सदस्यों, 66 ग्राम पंचायत प्रधानों, 35 क्षेत्र पंचायत सदस्यों तथा चार जिला पंचायत के वार्डो पर चुनाव प्रक्रिया गतिमान है।

नामांकन प्रक्रिया शुरू होते ही चुनावी सरगर्मिया तेज हो गयी है तथा मुख्य बाजारों से लेकर गांव की चौपाल तक चुनाव की चर्चाएं शुरू हो गयी है। क्षेत्र पंचायत प्रमुख का पद सामान्य होने तथा प्रमुख पद पर दावेदारी करने वालों की क्षेत्र पंचायत सदस्य की सीट आरक्षित होने से प्रमुख पद पर आसीन होने वाले लोगों के अरमान धरे के धरे रह गये है फिर भी प्रमुख पद पर आसीन होने के लिए अभी से बिसात बिछनी शुरू हो गयी है तथा सत्ताधारी भाजपा व विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस के लिए प्रमुख की सीट प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है। जिला पंचायत के चारो वार्डो पर भी घमासान मचने की पूर्ण सम्भावना बनी हुई है। राष्ट्रीय दलों ने भले ही जिला पंचायत के चारो वार्डो पर प्रत्याशियों को अधिकृत करने में विलम्ब किया हो, मगर राष्ट्रीय दलों से अधिकृत होने के लिए गुणा-भाग का खेल शुरू हो गया है। जिला पंचायत के परकण्डी वार्ड को इस बार भी सामान्य महिला के लिए आरक्षित होने पर इस वार्ड से निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य रीना बिष्ट, पूर्व जिला पंचायत सदस्य मीना पुण्डीर, प्रीति पुष्वाण, सोनिया नेगी, शशि सेमवाल व विजय लक्ष्मी त्रिवेदी की दावेदारी प्रमुख मानी जा रही है, जबकि प्रीति पुष्वाण ने अपना चुनावी बिगुल बजाकर चुनावी प्रचार शुरू कर दिया है। जिला पंचायत के कालीमठ वार्ड को भी सामान्य महिला हेतु आरक्षित होने पर इस वार्ड पर निवर्तमान क्षेत्र पंचायत सदस्य कोटमा सोमेश्वरी भट्ट, पूर्व जिला पंचायत सदस्य संगीता नेगी व सरोज राणा, निवर्तमान प्रधान पाली सरूणा प्रेमलता पन्त की दावेदारी प्रमुख मानी जा रही है। जिला पंचायत के चारों वार्डो पर कितने प्रत्याशी चुनावी समर में रहते हैं, यह तो नाम वापसी के बाद ही स्पष्ट हो पायेगा, मगर चारों वार्डो पर जीत दर्ज करने के लिए प्रत्याशियों ने मतदाताओं को रिझाने का काम शुरू कर दिया है। ■■■

दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर एक जुलाई से नियम लागू

स्टेट ब्यूरो

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक कड़ा फैसला लेते हुए एंड ऑफ लाइफ (ईओएल) घोषित वाहनों को ईंधन देने पर रोक लगा दी है। यह नीति उन वाहनों पर लागू होती है, जो डीजल के मामले में 10 साल और पेट्रोल या सीएनजी के मामले में 15 साल से अधिक पुरानी हो चुकी हैं।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देशों के तहत इस कदम को लागू किया गया है, जिसे दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग, ट्रैफिक पुलिस, नगर निगम और दिल्ली पुलिस मिलकर प्रभावी बना रहे हैं। राजधानी के लगभग 350 पेट्रोल पंपों पर निगरानी के लिए ट्रैफिक पुलिस और सिविल डिफेंस कर्मियों को तैनात किया गया है। सभी पंपों पर हाई-टेक 'ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन' सिस्टम लगाए गए हैं, जो वाहनों की नंबर प्लेट स्कैन कर उन्हें केंद्रीय वाहन डेटाबेस से मिलाते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि कितनी उम्र की गाड़ी फ्यूल लेने पहुंची है।

यदि गाड़ी तय आयु सीमा से अधिक पुरानी है, तो उसे पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। फिलहाल सीएनजी स्टेशनों को इस निगरानी दायरे से बाहर रखा गया है, लेकिन भविष्य में उन्हें भी शामिल किया जा सकता है।

यदि कोई ईओएल वाहन फ्यूल पंप पर आता है और नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो पहली बार में वाहन मालिक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दोपहिया वाहनों के लिए यह राशि 5,000 रुपये निर्धारित की गई है। वाहन मालिक को एक बार चेतावनी देकर यदि उसके बाद भी वाहन चलता पाया गया, तो उसे स्थायी रूप से जब्त कर लिया जाएगा और स्क्रैप प्रक्रिया के तहत नष्ट कर दिया जाएगा। ■■■

यूकेएसएसएससी ने बदली परीक्षा की तिथियां

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) ने राज्य में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के चलते आगामी भर्ती परीक्षाओं के कार्यक्रम में अहम बदलाव किया है।

आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, आरक्षी (जनपदीय पुलिस व पीसीआईएबी पुरुष) पद के लिए प्रस्तावित लिखित परीक्षा 03 अगस्त को, प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला सहायक (रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, उद्यान विज्ञान व पशुपालन विभाग)/ मशरूम पर्यवेक्षक वर्ग-3 लिखित परीक्षा 09 अगस्त को और फोटोग्राफर, स्नातक सहायक, प्रतिरूप सहायक, वैज्ञानिक सहायक की परीक्षा अब 10 अगस्त को आयोजित की जाएगी। ■■■

2025-26 REGISTRATION NOW OPEN FOR GRADE 11

The best school in the town with professional service

ABOUT US

The school comes with an uncompromising commitment. It aims to achieve specific measurable observable and quantitable results among all aspirants/students because the school has a vision to provide value based education to young minds and provide a dynamic learning environment.

OUR FACILITIES

The School Provide All Basic Facilities Each Student. Indoor And Outdoor Sports Are Provided By School.

- Composite Science Lab
- Physics Lab
- Chemistry Lab
- Biology Lab
- Maths Lab
- Computer Science Lab
- Home Science Lab
- Library
- Other Rooms

Streams offered:

- Humanities
- Commerce
- Science

Grade Nursery to 12th

Visit our facebook page or website for more
https://www.facebook.com/shemfordSrinagar
srinagar-garhwal.shemford.com

Call To find out more
9568450335, 7895938233

Email
srinagar@shemford.com